

## कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- पीएमजीएसवाई/2019-20/डी-4325

दिनांक: 24/04/19

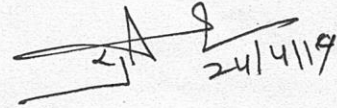
परिपत्र 02/2019-20

विषय:-14 वी विधानसभा की जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 के 265 वें प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या-5 के क्रियान्वयन बाबत।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के दिशा निर्देश के अनुच्छेद 4.1 में प्रावधान है कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को व्यवस्थित और प्रभावी लागत से प्राप्त करने हेतु समुचित कार्य योजना आवश्यक है, अनुच्छेद 11.5 में प्रावधान है कि उन मामलों में जहाँ सविंदा की लागत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किये गये अनुमानों से अधिक है, राज्य के लिए एक फेज/बेंच में स्वीकृत किये गये कार्यों पर समग्र अंतर (टेंडर प्रीमियम) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावे।

अतः 14 वी विधानसभा की जन लेखा समिति वर्ष 2018-19 के 265 वें प्रतिवेदन (सीएजी प्रतिवेदन 2015-16 आर्थिक क्षेत्र अनुच्छेद संख्या 3.8) की सिफारिश संख्या 5-(प्रतिलिपि संलग्न) का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में ही सड़क का सही सर्वे कर एवं लागत को प्रभावित करने वाले समस्त बिन्दुओं का समावेश कर डीपीआर तैयार की जावे। ताकि भविष्य में डीपीआर की लागत में बदलाव न हो।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।



(सुनील कुमार गुप्ता )

मुख्य अभियन्ता, (पीएमजीएसवाई)

क्रमांक:- पीएमजीएसवाई/2019-20/डी-

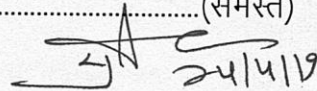
दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1.अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग - .....(समस्त)

2.अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त - .....(समस्त)

3.अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड - .....(समस्त)



मुख्य अभियन्ता, (पीएमजीएसवाई)